UNIT 2

GENDER AND SEX EQUALITY

TOPIC : SEX RATIO

देश में लगातार दूसरे साल जन्मदर में कमी आई है. इलाज की बेहतर सुविधा से मृत्यु दर भी घटी है. हालांकि, चिंता की बात यह है कि लिंगानुपात और घट गया है. लाख कोशिशों के बावजूद देश में लिंगानुपात बढ़ाने की कोशिश सफल नहीं हो रही है. 2014-2016 के दौरान लिंगानुपात 898 था. 2015-17 के दौरान यह 896 पर आ गया.

लिंग अनुपात से मतलब यह है कि देश में प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है. 2015-17 के दौरान 896 लिंगानुपात का मतलब यह है कि देश में प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है.

2011 की जनगणना में लिंगानुपात 940 था. 2017 के एसआरएस सर्वे के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में जन्म के समय लिंगानुपात 961 था, जो देश में सबसे ज्यादा था. हरियाणा में यह आंकड़ा 833 था, जो देश में सबसे कम था.

अधिकारियों ने बताया कि इस रिपोर्ट में 31 दिसंबर, 2017 तक के आंकड़े शामिल हैं. यह सर्वे 2018 में किया गया. इसके नतीजें 2019 में सार्वजनिक किए गए हैं. सर्वे के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड बर्थ रेट (सीबीआर) 2017 के दौरान 20.2 रहा. 2016 के मुकाबले यह 0,2 अंक कम है.

जन्म दर का मतलब किसी एक साल में प्रति 1000 आबादी में जन्म लेने वाले बच्चों (जीवित) की

संख्या से है. सबसे ज्यादा सीबीआर बिहार (26.4) का है. केरल में यह सबसे कम (14.2) है.

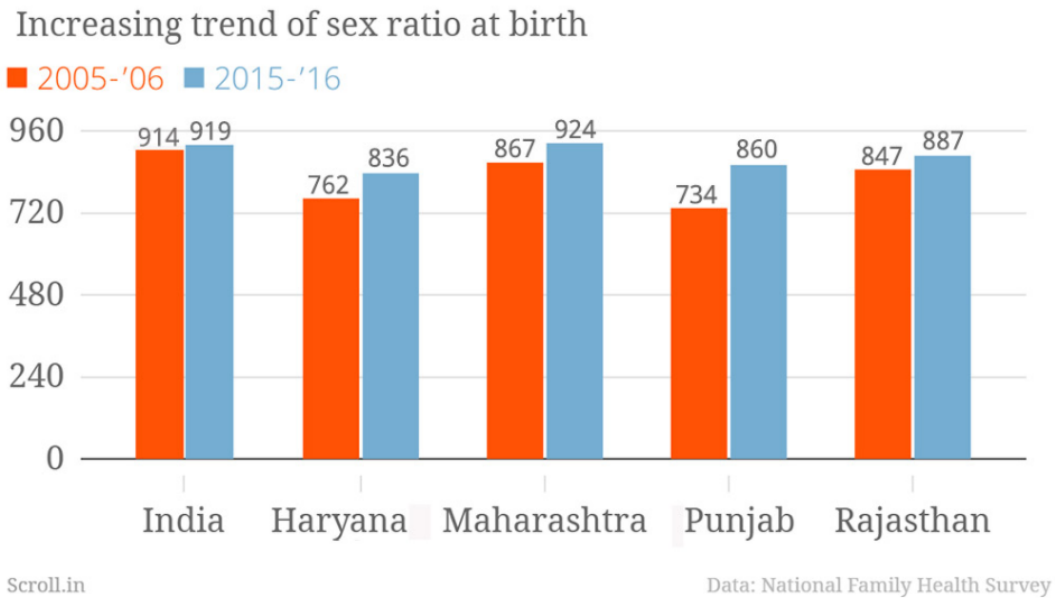

जन्म के समय लिंगानुपात समान नहीं है: प्रत्येक देश में जन्म पुरुष-पक्षपाती होते हैं। जैविक कारण हैं कि लड़कियों की तुलना में हर साल थोड़े अधिक लड़के पैदा होते हैं। जन्म के समय boys प्राकृतिक 'लिंग अनुपात प्रति 100 लड़कियों पर लगभग 105 लड़कों (लगभग 103 से 107 लड़कों तक) है।

कुछ देशों में, जन्म के समय लिंग अनुपात प्राकृतिक रूप से होने की तुलना में बहुत अधिक तिरछा है। आज और हाल के दिनों में यह विशेष रूप से एशिया और उत्तरी अफ्रीका में आम है। यहां प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और चयनात्मक गर्भपात के माध्यम से लिंग चयन के स्पष्ट प्रमाण हैं।

जिन देशों में स्पष्ट बेटे की प्राथमिकता होती है, वहां जन्म के समय लिंगानुपात जन्म के क्रम के साथ बढ़ता जाता है (तीसरे या चौथे जन्म के बच्चे पहले या दूसरे बच्चे की तुलना में लड़के होने की संभावना अधिक होती है)।

लगभग हर देश में, लड़कियों की तुलना में लड़कों के बचपन में मरने की संभावना अधिक होती है। इसके जैविक कारण हैं: लड़के जन्मजात जटिलताओं और संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

उन देशों में जहां पुत्र की प्रबलता है, लड़कियों के लिए मृत्यु दर अधिक होने की उम्मीद है: यह प्रत्यक्ष रूप से शिशु हत्या के माध्यम से हो सकता है, लेकिन उपेक्षा और असमान उपचार के माध्यम से भी हो सकता है।

2015 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्या भ्रूण और बालिकाओं दोनों के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को हरियाणा के पानीपत में बंद कर दिया गया था, एक राज्य जहां 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात 1,000 लड़कों के लिए सिर्फ 834 लड़कियां थीं। तब से, राज्य सरकार ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत अपराधियों, डॉक्टरों, क्वैक डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रयोगशाला तकनीशियनों के खिलाफ 400 से अधिक मामले दर्ज किए हैं।

लिंगानुपात जीवन के पाठ्यक्रम (पुरुष-पक्षपाती बनने से लेकर महिला-पक्षपाती) तक कम हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं।

यह अनुमान है कि आज चयनात्मक गर्भपात और अतिरिक्त महिला मौतों के परिणामस्वरूप दुनिया में 130 मिलियन से अधिक in लापता महिलाएं 'हैं।

लिंग निर्धारण स्कैनिंग और लिंग-चयन गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने से कुछ देशों में जन्म के समय लिंग अनुपात में वृद्धि सीमित हो सकती है, लेकिन इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है।

विकास का लिंगानुपात पर पड़ने वाले प्रभावों का विरोध हो सकता है: इस बात के प्रमाण हैं कि पुत्र की प्राथमिकता शिक्षा के साथ गिरावट आती है, लेकिन यह अक्सर प्रजनन दर में गिरावट और चयनात्मक तकनीकों तक पहुंच में वृद्धि (जिससे लिंग अनुपात में वृद्धि हो सकती है) के साथ हाथ से जाता है।

हमारी सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रभावी उपाय निम्नानुसार हैं:

सरकार ने लिंग संवेदनशील नीतियों, प्रावधान और कानून के माध्यम से बालिकाओं को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक बहु-प्रचारित रणनीति, योजनाओं, कार्यक्रमों और जागरूकता सृजन / वकालत के उपायों को अपनाया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत और इसकी छत्रछाया में प्रजनन और बाल स्वास्थ्यप्रणाली, लिंग अनुपात में सुधार के लिए कई हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं।

उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

· गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन पर प्रतिबंध, और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के नियमन के लिए, सरकार ने एक व्यापक कानून, प्री-गर्भाधान और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम 1994 में अधिनियमित किया था। 2003 में और संशोधन किया गया।

· सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को तेज कर दिया है और सीलिंग और जब्ती के प्रावधान और अपंजीकृत मशीनों को जब्त करने और अपंजीकृत क्लीनिकों के खिलाफ सजा देने के लिए विभिन्न नियमों में संशोधन किया है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरणों के उपयोग के विनियमन को केवल पंजीकृत परिसर के भीतर अधिसूचित किया गया है। एक जिले के भीतर अधिकतम दो अल्ट्रासाउंड सुविधाओं में अल्ट्रासोनोग्राफी आयोजित करने के लिए चिकित्सा चिकित्सकों पर प्रतिबंध रखा गया है। पंजीकरण शुल्क बढ़ाया गया है। कर्मचारियों, स्थान, पते या उपकरण में परिवर्तन के लिए अग्रिम सूचना प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने और अवैध रूप से उपयोग को रोकने के लिए समय पर कदमों का अनुरोध किया है। प्रधान मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बाल लिंगानुपात में गिरावट की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए व्यक्तिगत नेतृत्व प्रदान करने और शिक्षा और सशक्तीकरण पर ध्यान देने के माध्यम से बालिकाओं की उपेक्षा को दूर करने का आग्रह किया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिनियम के गंभीर कार्यान्वयन पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रेरित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

PCPNDT अधिनियम के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (CSB) का पुनर्गठन किया गया है और नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वेबसाइटों पर सेक्स चयन विज्ञापनों को अवरुद्ध करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया है।

राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति (NIMC) का पुनर्गठन किया गया है और अल्ट्रासाउंड नैदानिक सुविधाओं के निरीक्षण तेज किए गए हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में निरीक्षण किए गए हैं।

राज्यों को सलाह दी गई है कि कारणों का पता लगाने के लिए कम बाल लिंग अनुपात वाले जिलों / ब्लाकों / गांवों पर ध्यान दें, उचित व्यवहार परिवर्तन अभियानों की योजना बनाएं और प्रभावी रूप से पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करें। धार्मिक नेताओं, महिलाओं को प्राप्त करने वालों आदि को तिरछे बाल लिंगानुपात और बालिकाओं के भेदभाव के खिलाफ अभियान में शामिल किया जा रहा है।

सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।